पेज थ्री देहरादून

डॉ निशंक की अध्यक्षता में "दिशा" की बैठक आयोजित की।

हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज होगा विशाल धरना–प्रदर्शन

संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आगामी एक मार्च, 2020 को प्रातः 11 बजे दून के गांधी पार्क में विशाल धरना–प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने बताया कि एक ओर राज्य सरकार द्वारा गरीब जनता के आवागमन का साधन रोड़वेज की बसों के किराये, भवन कर, बिजली पानी के करों में वृद्धि कर मंहगाई बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों पर भर्ती परीक्षा में घोटाले को अंजाम देकर प्रदेश के युवाओं से छलावा कर रही है।

शिवम चमोली इंटक कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

संवाददाता देहरादून। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुन्दरियाल ने शिवम चमोली को इंटक कांग्रेस उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और कहा कि श्रमिकों के हितों के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किये जा रहे है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुन्दरियाल ने शिवम चमोली को इंटक कांग्रेस उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर सुन्दरियाल ने नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से अपेक्षा की है कि वह इंटक की नीतियों को लेकर श्रमिकों के बीच जाकर श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए हरसंभव प्रयास करेंगें और इंटक की मजबूती के लिए कार्य करेंगें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेता बनने के लिए जड़ का मजबूत होना आवश्यक होता है। इस अवसर पर अनेक सदस्य उपस्थित थे।

मेजर शशि मेहता करेंगी 14 अगस्त को 111 किमी दौड़ में प्रतिभाग

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी मेजर शशि मेहता ने कहा है कि मन में हौसला होने से कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की महिलाओं को अपने हुनर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगामी 14 अगस्त को लेह में 111 किलोमीटर में दौड़ में प्रतिभाग करेगी लेकिन इस दौड़ में वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और खेल मंत्री अरविन्द पांडेय से मिलकर आर्थिक सहायता की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि वह एक एनसीसी अधिकारी है और देहरादून की निवासी है तथा वर्तमान समय में सहारनपुर में कार्यरत है।

आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए सुविधा होगी: सीएम

शिलान्यास

■ उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास

देहरादून। **संवाददाता**

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को आईटी पार्क देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। उत्तराखण्ड भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इससे आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए सुविधा होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। यह देश का इस तरह का आपदा प्रबंधन के लिए दूसरा भवन होगा। इस भवन में 06 फ्लोर बनाए जायेंगे। जिनमें प्रशिक्षण हॉल, कांफ्रेंस हॉल, स्टेट ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अन्य कक्षों के निर्माण किये जायेंगे। यह भवन 11715 वर्ग मीटर में बनाया जायेगा। यह भवन जनवरी 2022 तक बनकर तैयार हो जायेगा।

इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक गणेश जोशी, प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरूगेशन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रिद्धिम अग्रवाल, निदेशक आपदा प्रबंधन पियूष रौतेला आदि उपस्थित थे।

गैरसैंण चमोली में आरम्भ हो रहे विस सत्र के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी नहीं मिलगा अवकाश

संवाददाता देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीन समस्त विभागाध्यक्षों को आदेश कर दें कि आगामी 03 मार्च, 2020 से गैरसैंण चमोली में आरम्भ हो रहे विधानसभा सत्र के दृष्टिगत किसी अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जाए क्योंकि इस अवधि में अपेक्षित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तथा विधानसभा से सम्बन्धित अन्य वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। अतः विषम परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

मुख्य सचिव ने बैंकर्स को दिए ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश

समीक्षा

संवाददाता

ऋण योजनाओं के लिये ऑनलाइन पोर्टलों के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लम्बित प्रकरणों पर समीक्षा बैठक आयोजित

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लम्बित प्रकरणों विषयक समीक्षा करते हुए सीएस।

देहरादून। सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लम्बित प्रकरणों विषयक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के लिये ऑनलाइन पोर्टलों के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा की गई। एजीएम आरके पंत ने बताया कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल बन गये हैं। उन्होंने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे तथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु विभाग द्वारा विगत 20 फरवरी को ऑनलाइन पोर्टल के लाइव डेमो हेतु कार्यशाला की गयी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में बैंक द्वारा दिये गये सुझावों को समाहित करते हुए इस पोर्टल का क्रियान्वयन हो जायेगा।

डे–नल्म केंद्रीकृत पोर्टल के सम्बन्ध में अवगत कराया कि इस पोर्टल में केवल अवालोकन करने का ही प्राविधान है, इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग से सपोर्ट पोर्टल बनाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है जिसमें बैंक शाखायें आंकड़ों को एडिट एवं अपडेट कर सकेंगी और बैंक तद्नुसार कार्यवाही कर सकेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्य सचिव द्वारा नये स्वयं सहायता समूह की स्वीकृति एवं समूहों के नवीनीकरण पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित पोर्टल में निरस्तीकरण के कारण का नया कालम बनाने के निर्देश दिये ताकि सम्बन्धित विभाग द्वारा कारण का निराकरण किया जा सके तथा समीक्षा भी की जा सके। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने वार्षिक लक्ष्य 300 को कम बताते हुए कम उपलब्धि वाले क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों के स्पष्टीकरण के निर्देश अपर सचिव पर्यटन को दिये। दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस पर व्यक्तिगत रूचि से कार्य करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये। उन्होंने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिये व्यक्तिगत प्रयास करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि योजना में 214 आवेदन पत्रों में से 82 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए तथा 97 आवेदन पत्र निरस्त तथा 35 आवेदन पत्र लम्बित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अपर सचिव आवास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वर्तमान में योजना में 2888 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा सुदूर क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर मार्च तक अवशेष लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा दिये गये।

सीएस ने की उत्तराखण्ड कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

संवाददाता देहरादून। सचिवालय सभागार में शुक्रवार को उत्तराखण्ड कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रभारी सचिव कौशल विकास रणजीत सिन्हा ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारत सरकार द्वारा 48236 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 69 विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण में 27919 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 22198 युवाओं को प्रमाणित किया जा चुका है एवं 9142 प्रशिक्षित युवा विभिन्न उद्यमों में नियुक्ति प्राप्त कर चुके है। साथ ही 19 हजार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि पलायन वाले जनपदों यथा पौड़ी, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में नीति आयोग की संस्तुति का संज्ञान लेते हुए स्थानीय उत्पादों आधारित रोजगार परक व्यवसायों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की बहुत सम्भावनायें हैं, जिसको देखते हुए स्किल डेवलपमेंट स्क्रीम में सेवा क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बल दिया जाए। प्रभारी सचिव रणजीत सिन्हा ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।